

- 1 B
Ex. भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा "असंगठित श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस" (NDUW) तैयार करने के लिए इस पोर्टल को प्रारंभ किया गया है। इसमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, कौशल व योग्यता व परिवार संबंधित विवरण उपलब्ध है।
- 2 C
Ex. ये ऐसी संस्थाएँ हैं, जो वित्तीय संस्थाओं के मध्य उधारकर्ताओं के वित्तीय लेन-देन के आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं।
- 3 B
Ex. कर्नाटक व आंध्र प्रदेश सर्वाधिक सौर-ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। विदित है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 450 जी.डब्ल्यू. हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 4 C
Ex. एफ.पी.सी. का गठन किसी भी या अधिक प्राथमिक उत्पादकों या दो या अधिक उत्पादक संस्थाओं, या दोनों के सहयोग से किया जा सकता है। इस प्रकार एफ.पी.सी. सहकारी-संस्थाओं और निजी कंपनियों का मिश्रित रूप है। एफ.पी.सी. का पंजीकरण "भारतीय कंपनी अधिनियम" के तहत होती है।
- 5 C
Ex. USOF, भारत के ग्रामिण व दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त व गैर-विभेदकारी दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किया गया है।
- 6 D
Ex. PLFS, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी होता है जबकि "त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण श्रम-ब्यूरो द्वारा प्रकाशित होता है।
- 7 D
Ex. "दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड-2016" के मूल ढांचे में ही प्री-पैकी की सिफारिश की गई है। इसमें सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान का प्रावधान है।
- 8 B
Ex. RBI द्वारा 1 जनवरी, 2021 को उक्त सूचकांक को जारी किया गया जिसमें 5 भुगतान मानदण्डों को अपनाया गया है।
- 9 B
Ex. हाल में बैंकों द्वारा सरकारी बॉण्ड में निवेश को वरियता दी गई। जबकि आर्थिक हालातों के अनुरूप अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था को उभारने का प्रयास करना चाहिए।
- 10 D
Ex. UPA सरकार द्वारा 2005-10 के मध्य तेल कंपनियों को 1.4 लाख करोड़ का Oil-Bond' जारी कार्ड रोजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया गया ताकि सब्सिडी देने से बचा जा सके। अर्थात् सब्सिडी देने से घाटा बढ़ जाता, अतः बदले में Bond दे दिया गया और Bond की परिपक्वता तक उस पर उन्हें ब्याज दिया गया परिपक्व होने पर सब्सिडी का भुगतान।
- 11 B
Ex. MSF, RBI की योजना है जिसके तहत बैंक RBI से अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त करते हैं। यह अल्पकालीन ऋण होता है। जो सरकारी प्रतिभूतियों के बदले प्राप्त होता है। किन्तु इस सुविधा का लाभ केवल तभी मिलता है, जबकि बैंकों द्वारा RBI की अन्य ऋण सुविधाओं जैसे-रेपो इत्यादि का लाभ लिया जा चुका है। इसकी दर रेपो दर से अधिक होती है।
- 12 B
Ex. "PM-KISAN" केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 6000 रु. की आर्थिक सहायता तीन बराबर किश्तों में हर चौथे महीने में किसानों को दी जाती है।
- 13 C
Ex. मुद्रा की आपूर्ति में कमी होने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
- 14 B
Ex. सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने के कारण पूंजी का प्रवाह निजी क्षेत्र से सरकार की ओर होता है, जिससे निवेश हतोत्साहित होता है, साथ ही सरकारी-व्यय बढ़ने से मुद्रास्फीति की संभावना भी प्रबल होती है।
- 15 B
Ex. यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक आर्थिक परिदृश्य व विकास पर फोकस किया जाता है, जिसमें उभरती व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- 16 D
Ex. NEFT के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर धन का अन्तरण RBI द्वारा संचालित होता है। जिसके लिए न्यूनतम सीमा का निर्धारण बैंकों द्वारा किया जाता है। RTGS और NEFT दोनों ही धन-अन्तरण की सुविधाएँ हैं। आमतौर पर RTGS के द्वारा 2 लाख रु. से अधिक का लेनदेन किया जाता है।
- 17 A
Ex. रेपो दर पर RBI बैंक को उधार देता है, जबकि रिवर्स-रेपो दर पर ऋण लेता है, किन्तु इसका उद्देश्य बैंकों की अतिरिक्त नकदी को अवशोषित करके तरलता की मात्रा को नियंत्रित करना है।
- 18 D
Ex. प्रायद्वीपीय पठार में छत्तीसगढ़ का मैदान ही नाम का एकमात्र मैदान है। यह एक तश्तरी के आकार का गड्ढा है जो ऊपरी महानदी द्वारा बहाया जाता है। पूरा बेसिन मैकला रेंज और ओडिशा पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह उत्तर में छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्व में रायगढ़ पहाड़ियों, दक्षिण पूर्व में रायपुर अपलैंड, दक्षिण में बस्तर पठार और पश्चिम में मैकला रेंज से घिरा है। इस क्षेत्र पर कभी हैतीवंशी राजपूतों का शासन था जिनके छत्तीस किलों (छत्तीसगढ़) से इसका नाम पड़ा। बेसिन चूना पत्थर और शैल्स के लगभग क्षैतिज बिस्तरों के साथ रची गई है। मैदान की सामान्य ऊंचाई पूर्व में 250 मीटर से लेकर पश्चिम में 330 मीटर तक है।

